because of the cooperation from the hon. Chairman, the Deputy Chairperson, the Vice-Chairmen, the leaders of various political parties and all my colleagues. I thank all of them wholeheartedly in this moment of my retirement from this House. Thank you.

MATTERS RAISED WITH PERMISSION OF THE CHAIR

Alleged victimisation of political opponents in Uttar Pradesh

प्रो. रामगोपाल यादव (उत्तर प्रदेश) : श्रीमन्, मैं एक बहुत ही गंभीर मसले पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश में विरोध की राजनीति करने वाले लोगों का जीवन असुरक्षित हो गया है।

श्रीमन्, लोकतंत्र में अगर विपक्ष नहीं है तो लोकतंत्र को लोकतंत्र नहीं कहा जा सकता, वह डिक्टेटरशिप में तबदील हो जाता है। जिस चीज़ का बहाना लेकर उत्तर प्रदेश में प्रमुख विपक्षी दल और अन्य विपक्षी लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है, मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष के नाम पर - 1980 से ही इसके लिए नियमावली है। उसमें समय-समय पर संशोधन होते रहे हैं और शुरू से लेकर अब तक देखा जाए तो लगभग हर मुख्यमंत्री ने एक ही तरीके से विवेकाधीन कोष का प्रयोग किया है। सी.ए.जी. ने उसकी जांच भी की है और अपनी रिपोर्ट भी दी है। उस रिपोर्ट को भी अगर आप देखें तो शुरू से लेकर अब तक जो ऐतराज़ भी किए हैं, वह हर कार्यकाल के एक जैसे हैं। लेकिन इसके बावजूद selective way में एक मुख्यमंत्री को single out करना और टेक्नीकल आधार पर कुछ मामलों में मुकदमा कराना, एक साथ ही... सर, मैं आपका ध्यान इसलिए आकर्षित करना चाहूंगा कि 3 जून, 1995 के बाद जब मुलायम सिंह मुख्यमंत्री नहीं रहे, उसके बाद से लेकर अब तक जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं, इससे पहले वे दो बार मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। इस बार भी मुख्यमंत्री बने हुए लगभग एक वर्ष हो चुका है। पहले भी जांचें हुई और जिला अधिकारियों ने तीन-तीन बार रिपोर्ट भेजी कि जो पैसा जहां गया उसका सदुपयोग हुआ है। केवल एक केस ऐसा आया जिसमें सीएजी और जिला मैजिस्ट्रेट ने भी रिपोर्ट लिखी, जिस पर यह आरोप लगा कि उसने फंड का मिसयूज किया है - महात्मा ज्योतिबा फूले ट्रस्ट, मुजफ्फरनगर के चेयरमैन ने। सौभाग्य या दुर्भाग्य से वे मौजूदा मंत्रिमंडल, उत्तर प्रदेश में कैबिनेट मंत्री हैं जिन पर आरोप लगा। इसके अलावा एक भी केस नहीं है। जब समाजवादी पार्टी के लोगों ने कुछ विधायकों ने, उत्तर प्रदेश के महामहिम राज्यपाल को उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री के संबंध में दो सीडी, अलग-अलग समय पर दीं, इसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी अपने धैर्य को खो बैठीं। सारे हिन्दुस्तान ने देखा कि समय-समय पर, इसके बाद उन्होंने जिस तरह की धमकी दी-सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ अगर कोई व्यक्ति इस तरह की धमकी देता है तो तमाम कमजोर अधिकारी ऐसे होते हैं जो उसी लाइन पर अपने आप चलने लगते हैं। 13 मार्च को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं दलित की बेटी नहीं अगर मुलायम सिंह को सबक नहीं सिखाया। इसके बाद कहा कि पर्दाफाश रैली की जाएगी और रैली हुई। लेकिन जब कुछ नहीं

मिला तो 13/14 अप्रैल की रात्रि को उत्तर प्रदेश के लगभग 40 जिलों में लखनऊ से एक सीनियर आईएएस आफिसर को भेजा गया, उन्होंने संबंधित जिला अधिकारियों पर दबाव डालकर कुछ एफआईआर दर्ज कराए। 14 अप्रैल को माननीय मुख्यमंत्री जी जिस वक्त घोषणा कर रही थी कि इतने मामलों में मुलायम सिंह के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, श्रीमन्, उस वक्त वे सब एफआईआर दर्ज नहीं हुई थीं। मेरे पास रिकार्ड है कि अकेले इटावा जिले में जहां सिर्फ 25 एफआईआर दर्ज हुई हैं, ये एसपी के दस्तखत से हैं। इसमें जब मुख्य मंत्री ने घोषणा की, उसके बाद की सब एफआईआर हैं। लेकिन मुख्यमंत्री ने कहा कि एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। यह अधिकारी एफआईआर का एक ही प्रोफार्मा सब जगह लेकर गया था। जिसमें फिल अप दि ब्लेंक्स करके एसडीएम ने सब जगह दस्तखत किए थे। आपको यह जानकार आश्चर्य होगा कि हमारे पास जो इटावा जिले का रिकार्ड है उसमें एक ही एसडीएम ने एक ही टाइम पर दो-दो थानो मे कई-कई रिपोर्टें लिखवाई हैं जब कि थानों की दूरी आधे घंटे की है। नियम यह है कि रिपोर्ट करने वाला थानो के अंदर जाएगा, एसडीएम थाने के अंदर जाएगा, तो एट ए टाइम दो जगह कैसे उपस्थित रह सकता है? मेरे पास एसपी का रिकार्ड है कि एट ए टाइम दो थानो में पांच-पांच रिपोर्टें लिखी। समय एक ही है और एक ही आदमी रिपोर्ट लिखवाने वाला है। इतनी जल्दबाजी में रिपोर्टें लिखवाई गईं कि उन्होंने यह भी नहीं देखा कि जिन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई जा रही है उन्होंने पैसा लिया या नहीं लिया। 25 मामले इटावा जिले में दर्ज कराए गए और उनमें पांच मामले ऐसे हैं जिनमें पैसा कभी जारी ही नहीं हुआ। जिला अधिकारी इस बात से परेशान हैं कि ये लोग हमारे खिलाफ एफआईआर दर्ज कर सकते हैं लेकिन चीफ सैक्रेटरी कहता है कि करिए रिपोर्ट दर्ज। यह स्थिति है। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मौजूदा मुख्यमंत्री के खिलाफ भी सीएजी ने लिखा है कि केवल पहले पांच महीने के कार्यकाल में 145 मामलों में नियमों को तोड़कर मुख्यमंत्री विवेकाधीन कोष से पैसा दिया गया। लगातार यह चला आ रहा है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मुख्यमंत्री दूसरे मुख्यमंत्री पर व्यक्तिगत रंजिश के हिसाब से 14 अप्रैल को यह कहे कि जैसे रावण का वध करने के लिए राम पैदा हुए थे, वैसे मुलायम सिंह का वध करने के लिए मायावती पैदा हुई है। सत्ता के शिखर पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति जब यह कहे, श्री अमर सिंह जी हमारे राज्य सभा के सम्मानित सदस्य हैं, सभी लोगों ने टीवी पर सुना होगा, उनके लिए परसों ही यह कहा कि मेरे पास ऐसे-ऐसे लोग हैं, अगर अमर सिंह और मोहम्मद आजम खान ने अपनी बयानबाजी बंद नहीं की तो मैं अपने लोगो से इशारा कर दूंगी और इनकी बोलती हमेशा-हमेशा के लिए बंद कर दी जाएगी। इसका क्या अर्थ होता है, आप सब लोग अनुमान लगा लें। किसी व्यक्ति की बोलती हमेशा-हमेशा के लिए बंद करने का क्या मतलब है?...(**व्यवधान**)... हत्या करवा देंगी । माननीय अमर सिंह जी ने कहा कि बारह अपराधियों को जिला प्रशासन ने कचहरी से ले जाकर छुड़वा दिया । अलीगढ़ में बहुत बड़े अपराधी थे । अमर सिंह को मारने की सूचना मिली थी । लेकिन आज तक उत्तर प्रदेश में जिला प्रशासन से लेकर किसी अधिकारी ने इसका खण्डन नहीं किया और अलीगढ़ में किसी अधिकारी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई । सभापति जी, ये सारी चीजे हैं । मैं सदन से यह निवदेन करना चाहता हूं कि यह डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, अगर इस तरह से चलेगा तो चल नहीं सकता है । हम कहीं निकल नहीं सकते हैं, हमें धमकी दी जा रही है । हम सदन में डेमोक्रेटिक वे में काम करने वाले लोग हैं । हम भी इसका जवाब उस तरह से दे सकते हैं लेकिन देंगे नहीं । मैं आपके माध्यम से हिन्दुस्तान के सबसे बड़े सदन में सरकार से यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वह इस बात की कोग्निजेंस ले क्योंकि यह सरकार उस सरकार मे

शामिल है और आपके सहयोग के बिना वे सत्ता में नहीं रह सकती हैं । अगर लोकतंत्र को जिंदा रखना है, सबके साथ न्याय, समानता, फिजिकल लिबर्टी का अधिकार, आर्टिकल 19 और 21 रखना है तो यह करना होगा । माननीय गवर्नर, महामहिम राज्यपाल के खिलाफ इस तरह से कोई मंच से भाषण दे, क्या आपने उससे इस बात की कल्पना की होगी कि सत्ता के शिखर पर बैठी मुख्यमंत्री अपने ही गवर्नर के खिलाफ जांच के आदेश की बात करेंगी । यह बहुत गंभीर विषय है । मैं इसके लिए निवेदन कर रहा हूं, आज कोई आक्रामक बात नहीं करना चाहता हूं केवल निवेदन करना चाहता हूं कि अगर डेमोक्रेसी को जिंदा रखना है तो उत्तर प्रदेश में जो सरकार है उसे बर्खास्त करने के अलावा केंद्र की सरकार के पास और कोई रास्ता नहीं है ।

THE LEADER OF THE OPPOSITION (DR. MANMOHAN SINGH): Mr. Chairman, Sir, Parliamentary Democracy constitutes a basic feature of our Constitution, and for its success, both the Government and the Opposition have a major role to play. Unfortunately, what is happening today in Uttar Pradesh is a most alarming situation developing there. The hon. Chief Minister, and I say with all respect, is using her office to victimise political opponents in a manner which is setting very bad precedents about the successful functioning of Parliamentary Democracy in our country. It is essential that the Government must use all its influence it has with the Government of U.P. - as the ruling party at the Centre is in a coalition with the Government there, with the Chief Minister's party in Uttar Pradesh - that they should put a stop to what is happening. There is mass victimisation of political opponents, wholesale registration of cases, not sparing even a former distinguished Governor of the State even when, I think, article 361 of the Constitution gives the Governor of a State full protection against the type of prosecution which is being talked about. Sir, before it is too late, the Central Government must wake up to its responsibilities. The growing crisis of Governance today is hurting the pace of development and social harmony in the most populous State of our Union. Therefore, this House and particularly, the Government of India have a responsibility to this House, and the country at large that they must intervene before this rot spread and destroys the basic feature of our Constitution.

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज) : सभापति जी, प्रो. रामगोपाल यादव जी ने कुछ बहुत ही गंभीर तथ्य इस सदन के सामने रखे हैं । इस पर नेता विपक्ष ने भी अपना दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है । आप जानते हैं कि सरकार ऐसे मसले पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करे उससे पहले राज्य सरकार से तथ्यों की पुष्टि करना, उनकी जांच करना जरूरी होगा । इसलिए जो बातें यहां आई हैं मैं चाहूंगी कि गृह मंत्री जी को

इन सबसे अवगत करा दूं । वे राज्य सरकार से सारे तथ्यों की जानकारी लेने के बाद इस सदन में अपना पक्ष रखेंगे । ...**(व्यवधान)**...

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल) : सभापति जी, एक बात है...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : एक-एक करके बोलिए ।

SHRI NILOTPAL BASU : Mr. Chairman, Sir, first of all, I support what Mr. Ramgopal Yadavji and the hon. Leader of the Opposition has said. But, more importantly, we have seen here instances when the State Governments have given reports and on the basis of those reports actions have also been taken against the Governors for allegedly following the decisions of the State Government. So, there is a clear case of duplicity in so far as the Government's action is concerned. We want that the Government of India and the principal ruling party - BJP - of the NDA coalition at the Centre and which is also a partner in the ruling-coalition in U.P, must take us into confidence. Of course, there are aspects on which the State Government's opinion has to be sought. But, at the same time, this issue goes beyond the simple law and order problem of a State. This impinges on the very basic foundations of the Parliamentary democracy and there are public records. What Mr. Ramgopal Yadaji has related is this. Actually, many of these things are on record because things have been spoken before camera. Therefore, I think, this is an evasive reply. Sir, Sushmaji must assure us by what time the Government will take the House into confidence and come out with a statement clearly outlining what would be the approach of the Government of India to rectify this situation.

श्री सभापति : माननीय सदस्यगण...**(व्यवधान)**... एक मिनट आप बैठ जाइये । ...**(व्यवधान)**... आप भी बैठ जाइये । माननीय सदस्यगण, आप जानते हैं कि यह राज्य का विषय है और इस संबंध में एक बार सदन में चर्चा भी हुई है । उस चर्चा के आधार पर हमने एक मीटिंग में चार मैंबरों की एक कमेटी बनाई है - श्री प्रणब मुखर्जी, श्री कपिल सिब्बल, श्री फाली एस0 नारीमन और श्रीमती सुषमा स्वराज । यह कमेटी इस पर विचार कर रही है । ऐसी स्थिति में भी, इस मामले की सीरियसनैस को देखते हुए, मैंने एलाउ किया है । मुझे उम्मीद है कि इसी सीरियसनैस से गवर्नमेंट रेसपांस करेगी ।...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया (झारखंड) : सभापति महोदय, पश्चिम बंगाल में पंचायत के चुनाव होने हैं।

श्री सभापति : अभी एक मिनट आप ठहर जाइये । पहले यह तो खत्म हो जाए । ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : महोदय, यह बात तो आपने रख दी । आपने रूलिंग दे दी ।...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : मैंने रूलिंग तो दे दी ...**(व्यवधान)**...

श्री एस.एस. अहलुवालिया : महोदय ...**(व्यवधान)**... नॉमीनेशन फाइल नहीं करने दिए जा रहे हैं । ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : एक मिनट, आप बैठिए । ...**(व्यवधान)**... देखिए, यह कायदा नहीं है ...**(व्यवधान)**... एक मिनट, आप बैठ जाइये । देखिए, यह कायदा नहीं है कि जब मर्जी आए खड़े होकर कोई इश्यू उठा दे । इन्होने मुझे लिख कर दिया है । सारा मैटीरियल मेरे सामने है। पश्चिम बंगाल के मामले मे आज बात हुई थी । मैंने उनसे कहा था कि आप सारा मैटीरियल मुझे दे । मैं इसकी सीरियसनैस को देखूंगा और फिर एलाउ करूंगा । इसलिए मैं आज एलाउ नहीं करता ।

श्री जनेश्वर मिश्र (उत्तर प्रदेश) : महोदय...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : पंडित जी, अब मामला तय हो गया ।...**(व्यवधान)**... अब मामला तय हो गया ।

श्री जनेश्वर मिश्र : मैं उस पर नही जा रहा हूं ।

श्री सभापति : तो फिर...**(व्यवधान)**... एक मिनट ठहरिए ।

श्री जनेश्वर मिश्र : माननीय सभापति महोदय, मैं राज्य का विषय नही उठा रहा हूं, मैं राज्य सभा का विषय उठा रहा हूं ।...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : राज्य सभा मे उठा रहे हैं ।

श्री जनेश्वर मिश्र : नही, राज्य सभा का विषय, अपने अधिकार का विषय उठा रहा हूं । माननीय अमर सिंह जी हमारे पीछे बैठे हैं । यह दो दिन से बोल रहे हैं ।...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : देखिए, ये दोनो बाते आ गई हैं । मैं अमर सिंह जी को एलाउ करता, लेकिन जान-बूझ कर मैंने एलाउ नही किया । इसलिए नहीं किया कि द मैटर हैज़ आलरेडी बिन रेफर्ड बाय श्री यादव ।

श्री जनेश्वर मिश्र : हम लोग इस सदन मे कैसे काम करेंगे, यह हम आपसे जानना चाहते हैं?...**(व्यवधान)**...

श्री अमर सिंह : मान्यवर, हमारी सुरक्षा के लिए आप निर्देशित करिए, क्योंकि मेरी जान का खतरा है और स्पष्ट रूप से मुख्य मंत्री कह रही हैं ।

श्री सभापति : ठीक है, मैं इस संबंध मे सरकार से बात-चीत करूंगा ।...**(व्यवधान)**...

श्री गांधी आजाद (उत्तर प्रदेश) : महोदय...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : इसका जवाब देने की जरूरत नहीं है । गवर्नमेंट इस मामले को देख रही है। यूपी की गवर्नमेंट से भी वह जानकारी करेगी । इसलिए इसमें आपको कोई खंडन करने की आवश्यकता नहीं है ।...**(व्यवधान)**...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal) : Sir, the hon. Member Mr. Amar Singh is saying that he needs security.

DR. MANMOHAN SINGH : Mr. Chairman, Sir, the hon. Member of this House has stated that he faces a threat to his life. We expect the Government to take it very seriously.

श्री सभापति : मैंने आपके कहे बिना ही...**(व्यवधान)**... मेरी बात तो सुन लीजिए । आप मेरी बात सुनिए । आपके कहे बिना ही मैंने इनके संबंध मे कहा है...**(व्यवधान)**...

SHRI SURESH KALMADI (Maharashtra) : Sir, you must direct the Government to give full protection to Mr. Amar Singh.

DR. MANMOHAN SINGH : They should immediately ensure that they would take all possible steps. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति : वह बोल रही हैं, बोलने दीजिए ।...**(व्यवधान)**... आप बेफिक्र रहिए, अमर सिंह जी को इतना कमजोर मत मानिए ।...**(व्यवधान)**... देखिए मेरी बात सुनिए । वह जवाब दे रही हैं ।...**(व्यवधान)**... सुनिए, सुनिए ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, जैसे ही साथी अमर सिंह जी ने यहां यह बात रखी, आपने स्वयं पीठ से कहा कि मैं स्वयं सरकार से बात करूंगा । उसके बाद मेरे खड़े होने की तो कोई बात रह ही नहीं जाती ।...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप सरकार की प्रतिनिधि हैं ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : पीठ से स्वयं यह आदेश आया है । आप सभापति भी हैं, भारत के उप-राष्ट्रपति भी हैं और स्वयं आप कह रहे हैं कि मैं सरकार से बात करूंगा, तो उसके बाद किसी और आश्वासन की बात ही नही रह जाती है ।...**(व्यवधान)**... जहां तक...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप सुनिए तो सही ।...**(व्यवधान)**... आप सुनिए, यह क्या कह रही हैं।

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal) : The Chair should not be involved in it. It is the responsibility of the Government...*(Interruptions)*... Why is she dragging the Chair?...*(Interruptions)*... It is not the job of the Chair. ...*(Interruptions)*... She should speak on behalf of the Government. ...*(Interruptions)*...

श्री सभापति : उन्हें बोलने दीजिए ...**(व्यवधान)**... वोरा जी बैठिए ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : सभापति जी, सांसदो की सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है और मैं यहां आश्वस्त करती हूं...**(व्यवधान)**... मैं बोल रही हूं सुनिए, मैं बोल रही हूं सुनिए ...**(व्यवधान)**...

श्री सभापति : आप लोग बैठिए, गुस्सा मत करिए इतना । गुस्से के कारण ही ये बातें पैदा हो रही हैं...**(व्यवधान)**... अब यहां गुस्सा पैदा कर रहे हैं । उन्हे बोलने दीजिए ।

श्रीमती सुषमा स्वराज : महोदय, मैं स्वयं गृह मंत्री जी से जोकि भारत के उप-प्रधान मंत्री हैं, बात करूंगी कि सदन मे खड़े होकर अमर सिंह जी ने स्वयं यह कहा है कि उनकी जान को खतरा है । इसलिए उनकी सुरक्षा का विशेष प्रबंध किया जाना चाहिए ।

श्री सभापति : ठीक है । स्पेशल मेंशंस - श्री राजकुमार धूत ।

SHRI P.G. NARAYANAN (Tamil Nadu) : Mr. Chairman, Sir, I would raise...*(Interruptions)*...

SHRI RAJKUMAR DHOOT (Maharashtra): Sir, today, I want to raise a special...*(Interruptions)*...

MR. CHAIRMAN: I won't allow on this very subject. ...*(Interruptions)*... I won't allow. ...*(Interruptions)*... It will not go on record. ...*(Interruptions)*...

Statement reportedly made by the Prime Minister during his speech in Srinagar for improvement of relationship between India and Pakistan

SHRI PRANAB MUKHERJEE (West Bengal) : Sir, we read in the newspapers that the Prime Minister, during his speech in Srinagar, had